

डिजिटल टैक्स चुनौती पर देशों को चेतावनी

सीतारमण बोली – टैक्स पारदर्शिता अब अनिवार्य

साइबर जोखिमों पर अब वैश्विक एकजुटता जरूरी

नई दिल्ली, 03 दिसंबर. डिजिटल अर्थव्यवस्था जिस तेजी से दुनिया को बदल रही है, उसी रफ्तार से टैक्स सिस्टम पर नए दबाव भी बढ़ रहे हैं. नई तकनीकें, वैश्विक वित्तीय उत्पाद और सीमा रहित ऑनलाइन लेनदेन—ये सभी देशों के लिए ऐसी चुनौती बन गए हैं जिन्हें अकेले सुलझाना अब संभव नहीं.

इसी कड़ी में नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल फोरम ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पजेज की



18वीं बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक समुदाय को एक स्पष्ट संदेश दिया—डिजिटलाइजेशन, साइबर सुरक्षा और प्राइवैसी की चुनौतियां सामूहिक प्रयास से ही हल होंगी. सीतारमण ने कहा कि टैक्स पारदर्शिता उभरती अर्थ

वी रुकेगी. उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत अंतरराष्ट्रीय टैक्स सूचना आदान-प्रदान मानकों का पालन करने में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है और आधुनिक तकनीक व एआई के माध्यम से टैक्स प्रशासन को लगातार मजबूत किया जा रहा है. ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तेज दौर में टैक्स प्रशासन की भूमिका पहले से कहीं अधिक जटिल हो गई है.

चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बैठक के उद्घाटन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कहा कि दुनिया आज ऐसे बिंदु पर खड़ी है, जहां सीमा-पार वित्तीय गतिविधियाँ, डिजिटल पेमेंट्स और वचुअल निवेश पैटर्न पारंपरिक टैक्स ढांचे को चुनौती दे रहे हैं.

रुपये में गिरावट से कारोबार में लुढ़के शेयर बाजार

12.37 अंक पर गिरा
संसेक्स

27.30 अंक पर
लुढ़का निफ्टी

मुंबई, 03 दिसंबर. रुपये में ऐतिहासिक गिरावट से बुधवार को शुरूआती कारोबार में घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट रही. संसेक्स 12.37 अंक की बढ़त में 85,150.64 अंक पर खुलने के बाद लाल निशान में चला गया.

खराब लिखे जाते समय यह 248.67 अंक (0.29 प्रतिशत) नीचे 84,889.60 अंक पर था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 27.30 अंक



गिरकर 26,004.90 अंक पर खुला. खबर लिखे जाते समय यह 90.50 अंक यानी 0.35 प्रतिशत लुढ़ककर 25,941.70 अंक पर था. रुपये में ऐतिहासिक गिरावट से शेयर बाजार पर दबाव है. भारतीय मुद्रा आज सुबह 90.15 रुपये प्रति डॉलर के स्तर तक टूट गयी और फिलहाल 90.0950 रुपये प्रति डॉलर पर है. शेयर बाजारों में आईटी को छोड़कर सभी सेक्टरों में बिकवाली हावी रही.

एनबीसीसी और जीडीए के बीच समझौता

2300 आवासीय इकाइयाँ एवं 64 दुकानों का होगा पुनर्विकास

नई दिल्ली, 03 नवंबर. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने तुलसी निकेतन स्कीम एरिया के 642.82 करोड़ रुपये के पुनर्विकास हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौता ज्ञापन पर राजेश कुमार सिंह, आईएएस, सचिव, जीडीए और प्रदीप शर्मा, कार्यपालक निदेशक (इंजी.) एवं



आरबीजी-प्रमुख, व्यापार प्रसार लिमिटेड द्वारा औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। यह

गाजियाबाद में आधुनिक, संधारणीय शहरी रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 78,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तारित तुलसी निकेतन स्कीम एरिया जिसमें लगभग 2300 आवासीय इकाइयाँ एवं 64 दुकानें हैं, का स्व-संधारणीय मॉडल के आधार पर पूरी तरह से पुनर्विकास किया जाएगा। इस क्षेत्र के कुछ भाग का व्यावसायिक रूप से उपयोग करके इस पुनर्विकास को वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है।

समाचार विशेष

पटेल के बेटे की ललकार से कांग्रेस में हड़कंप



अहमदाबाद. कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले दिवंगत नेता अहमद पटेल के परिवार में सियासी घमासान छिड़ गया है. उनके बेटे फैसल पटेल ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा बम फोड़ा है, जिससे पूरी पार्टी में खलबली मच गई है. फैसल ने सार्वजनिक

दिल्ली से गुजरात तक कांग्रेस नेतृत्व की चिंताएं बढ़ी

रूप से ऐलान किया कि वह कांग्रेस को तोड़कर एक अलग गुट बनाने की योजना बना रहे हैं.

इस सियासी ड्रामे में उस वक नया मोड़ आ गया जब उन्होंने दावा किया कि उनकी बहन मुमताज भी उनके साथ आ सकती हैं, जिसने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया है. फैसल पटेल का यह बयान ऐसे बेहद नाजुक समय में आया है जब कांग्रेस पार्टी पहले से ही कर्नाटक में चल रही आंतरिक कलह और बिहार में मिली करारी चुनावी हार के जख्मों से जूझ रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे

उनके पोस्ट के स्क्रीनशॉट में फैसल ने साफ लिखा कि वह 'कांग्रेस (AP)' नाम से एक नया गुपु बनाना चाहते हैं. अहमद पटेल ताउम्र गांधी परिवार के वफादार और पार्टी के संकटमोचक रहे, ऐसे में उनके ही बेटे द्वारा पार्टी तोड़ने की बात करना सियासी गलियारों में तुफान ला रहा है. बता दें बिहार में कांग्रेस की मिली करारी हार के बाद से कांग्रेस पर तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं और इसके साथ ही पीएम मोदी ने बिहार में मिली ह्छ को प्रचंड जीत के बाद से पार्टी कार्यालय से कांग्रेस में एक और

कांग्रेस बनने और तमाम तरह की गुटबाजियों की बात की थी जो कि अब पीएम की यह भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है. फैसल ने जैसे ही अपनी बहन मुमताज पटेल को इस नए गुपु में शामिल करने का जिक्र किया, मुमताज ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और भाई के दावों की हवा निकाल दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर तुरंत सफाई दी और कहा कि उनका किसी भी नई राजनीतिक पार्टी या गुपु में शामिल होने का रती भर भी इरादा नहीं है.

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव का बजा बिगुल

तारीखों की घोषणा, बैलेट पेपर से मतदान

चंडीगढ़. पंजाब में एक बार फिर से चुनाव का बिगुल बज गया है. राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव की घोषणा हो गई है. 14 दिसंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए मतदान होगा और 17 को मतगणना होगी.

स्टेट इलेक्शन कमिशन राज कमल चौधरी ने शुक्रवार दोपहर बाद चुनावों की घोषणा की है. 4 दिसंबर तक नामांकन होंगे. खास बात यह है कि बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल होगा. वहीं चुनाव में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी. 5 दिसंबर को सभी



खास बात यह है कि चुनाव डीवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होंगे. पंचायत समिति के लिए सफेद रंग का और जिला परिषद के लिए पीले रंग का बैलेट पेपर होगा. जिला परिषद का प्रत्याशी 255000 और पंचायत समिति का प्रत्याशी 110000 चुनावी खर्च कर सकेगा. पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र के लिए तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है.

नामांकन पर्चों की स्कूटी होगी. 6 दिसंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. 6 दिसंबर को ही चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. चुनावों के लिए सूबे में 1 करोड़ 36 लाख 4650 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे. मतदान वाले दिन सुबह 8:00 बजे शुरू शाम 4:00 तक वोटिंग होगी. इसके अवाला नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी. 3528 संवेदनशील और 915 अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए हैं. 96000 कर्मचारियों और 50,000 पुलिस जवानों को चुनावी ड्यूटी पर लाया जाएगा. 21 साल से कम उम्र के लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

विशेष बीजेडी के वरिष्ठ नेता देवाशीष सामंतराय क्यों नाराज?



भुवनेश्वर. 2024 की दोहरी चुनावी हार के बाद बीजेडी लगातार टूट रही है. देवाशीष सामंतराय समेत कई नेता पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं और पद ठुकरा रहे हैं. वीके पांडियन पर भी आरोप लग रहे हैं. कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और माना जा रहा है कि सामंतराय भी जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं.

2024 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारने का ये अंजाम होगा.

रुपया 90 .30 प्रति डॉलर के नये निचले स्तर पर

मुंबई, 03 दिसंबर. रुपये में बुधवार को लगातार पांचवें दिन गिरावट रही और यह 90.30 रुपये प्रति डॉलर के नये निचले स्तर तक गिर गया. भारतीय मुद्रा पिछले कारोबारी दिवस पर 43.50 पैसे गिरकर 89.9650 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी. रुपया आज 89.96 रुपये प्रति डॉलर पर स्थिर खुला और 89.93 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ. दोपहर के समय यह 90.30 रुपये प्रति डॉलर तक उतर गया था. शाम 4.30 बजे भारतीय मुद्रा 22.75 पैसे नीचे 90.1925 प्रति डॉलर पर थी. बाजार में अभी कारोबार जारी है. विदेशी संस्थागत निवेशकों के भारतीय पूंजी बाजार से पैसा निकालने से रुपये पर दबाव रहा. इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से भी रुपया कमजोर हुआ.

ईसीओआर माल ढुलाई में अग्रणी

ट्रैफिक हैंडलिंग में 209 लाख टन का शानदार आंकड़ा हासिल किया

भुवनेश्वर, 03 दिसंबर. पूर्वी तटीय रेलवे (ईसीओआर) के खुर्दा रोड डिवीजन ने एक बार फिर अपनी अब तक की सबसे अच्छी लोडिंग क्षमता हासिल करते हुए रेलवे में माल ढुलाई में बेहतर प्रदर्शन करने वाले डिवीजन के तौर पर जगह बनायी है. यह डिवीजन लगातार रिकॉर्ड तोड़ नतीजे दे रही है, जो देश के माल ढुलाई और आर्थिक विकास में इसकी अहम भूमिका को दिखाता है.

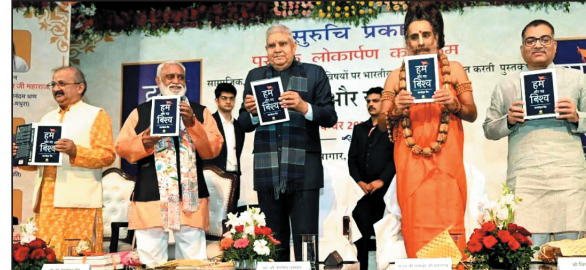
ईसीओआर के अधिकारियों ने कहा कि खुर्दा रोड डिवीजन कुल ट्रैफिक हैंडलिंग में देश में सबसे आगे है. नवंबर 2025 तक इसने 209 लाख टन का शानदार आंकड़ा हासिल किया है, जिसमें 115 लाख टन लोडिंग और 94



लाख टन उतराव शामिल है.बिलासपुर डिवीजन 169.6 लाख टन के साथ दूसरे स्थान पर रहा, उसके बाद धनबाद डिवीजन (152.8 लाख टन) और चक्रधरपुर डिवीजन (145.8 लाख टन) रहे.

डिवीजन ने सिर्फ 235 दिनों

में (21.11.2025 तक) 200 लाख टन सामान को प्रबंधित कर एक नया नेशनल बेंचमार्क बनाया है. यह भारतीय रेलवे में अब तक की सबसे तेज कामयाबी है, जिसने 2024-25 में 250 दिनों के अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.



पीएचडी की स्वर्ण कंसन्ट्रेट पर आयात शुल्क की सिफारिश

नई दिल्ली, 3 दिसंबर. पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योगमंडल (पीएचडीसीसीआई) ने स्वर्ण अयस्क कंसन्ट्रेट (एचएसएन 26169010) पर आयात शुल्क शून्य किये जाने और घरेलू सोना प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना शुरू करने की सिफारिश की है.

पीएचडीसीसीआई ने बुधवार को कहा कि स्वर्ण परिशोधन क्षेत्र की पीएलआई योजना से देश में सोने की उत्पादन क्षमता का विस्तार, तकनीकी उन्नयन और इस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी. पीएचडी की यह सिफारिश ऐसे परिप्रेक्ष में है जबकि भारत का

सोना उद्योग खपत के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है. भारत में सोने की अधिकशरा मांग आयात के माध्यम से पूरी होती है. पीएचडीसीसीआई ने वर्ल्ड गोल्ड कार्डंसिल की 2024 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि देश में 2024 में सोने की मांग में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इसका एक कारण आयात शुल्क में कमी भी थी.

पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष राजीव जुनेजा ने एक बयान में कहा कि भारत में 2025 के लिए सोने की मांग की संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं और अगले तीन वर्षों के दौरान देश की सोने के की मांग 700 से 800 टन वार्षिक के बीच रहने की उम्मीद है.

शुल्क को व्यावहारिक बनाये जाने की सिफारिश की

श्री जुनेजा ने यह भी कहा कि इस समय देश में जहां ताबे के अयरक कंसन्ट्रेट के आयात पर शुल्क शून्य है और इसके उप-उत्पाद के रूप में सालाना लगभग 12 टन सोने की प्राप्ति होती है, वहीं सोने के अयस्क कंसन्ट्रेट पर शुल्क अब भी 2 .5 प्रतिशत की दर के साथ ऊंचा रखा गया है. उन्होंने कहा, देश में स्वर्ण परिशोधन उद्योग के प्रोत्साहन के लिए इस पर शुल्क को व्यावहारिक बनाये जाने की सिफारिश की है. उनकी राय में सोने पर आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 2014-25 के बजट में 6 प्रतिशत करने से सोने का सीधे आयात घरेलू रीफाइनिंग की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक हो गए हैं .

एक नया लक्ष्य पीएम ने तय किया

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ समय से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं लेकिन अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के संबोधन में इसका जिक्र करना बहुत अहम है. वहां प्रधानमंत्री ने सिर्फ गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने की बात नहीं कही, बल्कि याद दिलाया कि अंग्रेजी राज में मैकाले ने एक सिस्टम बनाया, जिसके असर में देश मानसिक रूप से गुलाम होता गया.

उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने गुलामी के प्रतीकों, कानूनों को हटाना

शुरू किया है और लोगों की मानसिकता बदलने का गंभीर प्रयास किया है. इसके साथ ही उन्होंने एक नया लक्ष्य भी तय किया. उन्होंने बताया कि 190 साल पहले यानी 1835 में मैकाले ने गुलामी की मानसिकता के बोज रोपे थे. प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल में उस 'अपवित्र घटना' के दो सौ साल पूरे हो रहे हैं. उससे पहले भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना है. उन्होंने पहले से 2047 बयान में कहा कि विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया है और अब उसी में 2035 तक भारत को मैकाले मॉडल से हटा कर गुलामी की मानसिकता मिटाने का लक्ष्य भी तय किया है. वैसे भी लक्ष्य तय करने में क्या दिक्कत है!

